



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941

No. 636]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941

गृह मंत्रालय

(महिला सुरक्षा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 811(अ).—केन्द्रीय सरकार, कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया की सरकार पर लागू होंगे। भारत गणराज्य और सोमालिया संघ गणराज्य के बीच दिनांक 01.08.2017 को हस्ताक्षरित सजायाफ्ता कैदियों के अंतरण संबंधी करार का सम्पूर्ण पाठ निम्नवत है। भारत गणराज्य की सरकार द्वारा दिनांक 01.09.2017 को और फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया की सरकार द्वारा 14.10.2017 को इस करार की अभिपुष्टि की गई थी।

भारत गणराज्य और सोमालिया संघ गणराज्य के बीच सजायाफ्ता कैदियों के अंतरण संबंधी करार

भारत गणराज्य और सोमालिया संघ गणराज्य, जिन्हें इसमें इसके पश्चात संविदाकारी राष्ट्र कहा गया है; अपने अपने देशों में सजायाफ्ता कैदियों के सामाजिक-पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने की इच्छा से; और यह विचार करते हुए कि आपराधिक कृत्यों के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और सजा पाए विदेशी नागरिकों को अपने देश के अंदर अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान करके यह उद्देश्य पूरा किया जाना चाहिए; निम्नानुसार सहमत हुए हैं;

अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ:

(क) “अधिनिर्णय” का अभिप्राय सजा सुनाने वाले न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का निर्णय अथवा आदेश है;

(ख) “प्राप्तकर्ता राष्ट्र” का अभिप्राय वह राष्ट्र है जिसमें कि सजायाफ्ता व्यक्ति को अपनी सजा या उसकी शेष बची सजा काटने के उद्देश्य से अंतरित किया जा सकता है या किया गया है;

- (ग) “सजा” का अभिप्राय किसी भी प्रकार की सजा या कार्रवाई है जिसमें किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने दाण्डिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी को एक निश्चित कालावधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित किया गया हो या आजीवन कैद की सजा दी गई हो;
- (घ) “सजायाफ्ता व्यक्ति” का अभिप्राय वह व्यक्ति है जिसे किसी दाण्डिक न्यायालय, जिसमें कि संविदाकारी राष्ट्र में किसी निश्चित समय के लिए उनके कानून के तहत स्थापित न्यायालय शामिल है, द्वारा सुनाए गए निर्णय के तहत कैद की सजा दी गई हो।
- (ङ) “अंतरणकर्ता राष्ट्र” का अभिप्राय वह राष्ट्र है जहां किसी सजा पाए व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है या किया गया है।

अनुच्छेद-2

सामान्य सिद्धांत

1. किसी संविदाकारी राष्ट्र के भू-क्षेत्र में सजायाफ्ता किसी व्यक्ति को इस करार के प्रावधानों के अनुसार अधिरोपित सजा काटने के लिए दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के भू-क्षेत्र में अंतरित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए वह अंतरणकर्ता राष्ट्र या प्राप्तकर्ता राष्ट्र को इस करार के अंतर्गत अंतरित किए जाने की अपनी सहमति व्यक्त कर सकता है।
2. अंतरण का अनुरोध किसी ऐसे सजायाफ्ता व्यक्ति जो किसी संविदाकारी देश का नागरिक हो या किसी संविदाकारी देश के कानून के अनुसार सजायाफ्ता व्यक्ति की ओर से आवेदन करने के हकदार व्यक्ति द्वारा संविदाकारी देश की सरकार द्वारा विहित तरीके से संविदाकारी देश को आवेदन भेजकर किया जा सकता है।

अनुच्छेद-3

केंद्रीय प्राधिकरण

1. संविदाकारी राज्यों में इस करार के कार्यान्वयन के प्रभारी प्राधिकरण:
भारत गणराज्य : गृह मंत्रालय
सोमालिया संघ गणराज्य : फेडरल मिनिस्ट्री फॉर जस्टिस
2. यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी राष्ट्र अपने केंद्रीय प्राधिकरण में परिवर्तन करता है तो वह राजनयिक माध्यमों के जरिए इसे दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद-4

अंतरण की शर्तें

1. इस करार के अंतर्गत किसी भी सजायाफ्ता कैदी को निम्नलिखित शर्तों पर अंतरित किया जा सकता है:
 - (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का राष्ट्रिक हो;
 - (ख) सजायाफ्ता व्यक्ति को मौत की सजा न सुनाई गई हो;
 - (ग) फैसला अंतिम हो;
 - (घ) सजायाफ्ता व्यक्ति के विरुद्ध अंतरणकर्ता देश में कोई ऐसी आपराधिक कार्रवाई लंबित न हो, जहां उसकी उपस्थिति आवश्यक है;
 - (ङ) सजायाफ्ता व्यक्ति पर सैन्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो;
 - (च) अंतरण का अनुरोध प्राप्त होने के समय सजायाफ्ता व्यक्ति की कम से कम छह माह की सजा शेष हो या उम्रकैद की सजा भुगत रहा हो।
 - (छ) अंतरणकर्ता राष्ट्र में जिस कृत्य अथवा चूक के लिए सजा दी गई हो, वह प्राप्तकर्ता राष्ट्र में अपराध के रूप में दंडनीय हो या यदि उसके भू-क्षेत्र में ऐसा कृत्य होता तो उसे एक अपराध माना जाता;

- (ज) प्राप्तकर्ता राष्ट्र में सजायाफ्ता व्यक्ति की हिरासत का अंतरण, अंतरणकर्ता राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा अन्य किसी आवश्यक हित के प्रतिकूल नहीं होगा;
 - (झ) अंतरण पर सहमति किसी सजायाफ्ता व्यक्ति द्वारा या उसकी शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति या उसके उम्र को ध्यान में रखते हुए यदि दोनों में से कोई संविदाकारी राष्ट्र आवश्यक समझे तो उस राष्ट्र के कानूनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जोकि उसकी ओर से कार्य करने का हकदार हो, दी जा सकती है;
 - (ञ) अंतरणकर्ता तथा प्राप्तकर्ता राष्ट्र इस अंतरण के लिए सहमत हो;
2. आपवादिक मामलों में, अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता राष्ट्र सजायाफ्ता व्यक्ति द्वारा काटी जाने वाली सजा की शेष अवधि छह माह से कम हो तो भी अंतरण करने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद-5

जानकारी प्रदान करने का दायित्व

1. यदि किसी सजायाफ्ता व्यक्ति ने इस करार के अंतर्गत अंतरित किए जाने हेतु अंतरणकर्ता राष्ट्र में ऐसी रूचि व्यक्त की हो तो अंतरणकर्ता राष्ट्र प्राप्तकर्ता राष्ट्र को निम्नलिखित सूचना एवं दस्तावेज भेजेगा, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता राष्ट्र या अंतरणकर्ता राष्ट्र में से किसी ने यह निर्णय न ले लिया हो कि वे अंतरण पर सहमत नहीं होंगे:
 - (क) सजायाफ्ता व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं स्थान और उसके पते, यदि प्राप्तकर्ता राष्ट्र में कोई हो के साथक्त व्यसाथ पासपोर्ट की एक प्रति या कोई अन्य-िगत पहचान वाला दस्तावेज के साथ और जहां तक संभव हो सजायाफ्ता व्यक्ति के अंगुलियों के निशान;
 - (ख) उन तथ्यों का विवरण जिस पर सजा आधारित हो;
 - (ग) सजा का स्वरूप, उसकी अवधि और प्रारंभ होने की तारीख;
 - (घ) उस निर्णय की सत्यापित प्रति और कानून के संगत प्रावधानों की प्रति जिसके अंतर्गत सजायाफ्ता व्यक्ति को सजा सुनाई गई हो;
 - (ङ) सजायाफ्ता व्यक्ति के पूर्ववृत्त या उसके चरित्र के संबंध में कोई चिकित्सकीय, सामाजिक या अन्य रिपोर्ट, जहां उसके आवेदन के निपटान के लिए या उसकी गिरफ्तारी के संबंध में निर्णय लेने के लिए यह प्रासंगिक हो;
 - (च) ऐसी कोई अन्य सूचना जो प्राप्तकर्ता राष्ट्र अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट करे, ताकि वह इसके आधार पर अंतरण की संभावना पर विचार कर सके और वह सजायाफ्ता व्यक्ति को अपने कानून के अंतर्गत अंतरण के सभी परिणामों की सूचना दे सके।
 - (छ) अंतरित किए जाने वाले सजायाफ्ता व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुरूप उनकी ओर से कार्रवाई करने के हकदार किसी व्यक्ति का अनुरोध।
 - (ज) यह विवरण कि पहले कितनी सजा काटी जा चुकी है और साथ ही मुकदमा के पूर्व हिरासत की अवधि, माफी संबंधी कोई सूचना अथवा सजा प्रवर्तित करने से संबंधित कोई दूसरा प्रासंगिक कारक, और
 - (झ) अंतरणकर्ता राष्ट्र से सजायाफ्ता व्यक्ति के अंतरण से संबंधित विवरण।
2. इस करार के अंतर्गत किसी अनुरोध पर निर्णय के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता राष्ट्र अंतरणकर्ता राष्ट्र के निम्नलिखित सूचनाएं और दस्तावेज भेजेगा, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता अथवा अंतरणकर्ता राष्ट्र ने पहले ही यह निर्णय न ले लिया हो कि वह हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं होगा:
 - (क) यह विवरण अथवा दस्तावेज कि सजायाफ्ता व्यक्ति प्राप्तकर्ता राष्ट्र का राष्ट्रिक है;
 - (ख) प्राप्तकर्ता राष्ट्र के संगत कानून की एक प्रति जिसमें यह प्रावधान हो कि वह कृत्य अथवा चूक, जिसकी वजह से अंतरणकर्ता राष्ट्र में सजा दी गई है, प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुरूप अपराध हो अथवा यदि यह उसके भू-भाग में किया गया हो तो उसे अपराध समझा जाए;

- (ग) किसी सजायाफ्ता व्यक्ति के अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता राष्ट्र में सजा की अवधि और इसे लागू करने से संबंधित किसी कानून अथवा विनियम के परिणामों का विवरण तथा यदि लागू हो, तो इस करार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के अनुसार के परिणाम का विवरण;
- (घ) सजायाफ्ता व्यक्ति का अंतरण स्वीकार करने की प्राप्तकर्ता राष्ट्र की इच्छा और सजायाफ्ता व्यक्ति की शेष सजा को पूरी करने की वचनबद्धता; और
- (ङ) कोई अन्य सूचना एवं दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता राष्ट्र आवश्यक समझे।

अनुच्छेद-6

अनुरोध और उत्तर

1. अंतरण हेतु अनुरोध राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतरणकर्ता राष्ट्र के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में तथा विहित प्रपत्र में, यदि कोई हो, प्राप्तकर्ता राष्ट्र के केन्द्रीय प्राधिकरण को भेजा जाएगा। उन्हीं चैनलों के माध्यम से उत्तर भेजे जाएंगे।
2. प्राप्तकर्ता राष्ट्र अपने निर्णय के बारे में अंतरणकर्ता राष्ट्र को तुरंत सूचना देगा कि वह अंतरण हेतु किए गए अनुरोध के बारे में सहमत है अथवा नहीं।

अनुच्छेद-7

सहमति एवं इसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता राष्ट्र यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1(ङ) के अनुरूप अंतरण की सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसा स्वेच्छा से करता है और उसे इसके कानूनी नतीजों की पूर्ण जानकारी है। ऐसी सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता राष्ट्र के कानून द्वारा प्रशासित होगी।
2. अंतरणकर्ता राष्ट्र अथवा प्राप्तकर्ता राष्ट्र को यह सत्यापित करने का एक मौका देगा कि सहमति इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शर्तों के दी गई है।

अनुच्छेद-8

प्राप्तकर्ता राष्ट्र पर अंतरण का प्रभाव

1. इस करार के अनुच्छेदय कानून के तहत का सक्षम प्राधिकरण अपने राष्ट्रीकर्ता राष्ट्र में उल्लिखित शर्तों के तहत प्राप्त 9 यालय अथवा प्रशासनिक आदेशन्या, जैसा अपेक्षित हो, के माध्यम से सजा का प्रवर्तन जारी रखेगा।
2. इस करार के अनुच्छेद कर्ताधीन प्राप्तके प्रावधानों के अध्या 11 राष्ट्र के कानून के अनुसार सजा का प्रवर्तन किया जाएगा और वह राष्ट्र ही सभी उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद-9

सजा का सतत प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता राष्ट्र अंतरणकर्ता राष्ट्र द्वारा निर्धारित सजा के कानूनी स्वरूप और अवधि के संबंध में बाध्य होगा।
2. यदि सजा का स्वरूप और अवधि अथवा दोनों प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के संगत न हो तो वह राष्ट्र, अंतरणकर्ता राष्ट्र पूर्व सहमति से दी गई सजा को न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के द्वारा समान अपराध के लिए अपने कानून के अनुकूल बनाएगा, जहां तक इसके स्वरूप और अवधि का संबंध है, अनुकूल सजा, जहां तक संभव हो, अंतरणकर्ता राष्ट्र के फैसले द्वारा दी गई सजा के अनुरूप होगी। तथापि, अंतरणकर्ता राष्ट्र द्वारा दी गई सजा के स्वरूप अथवा अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद-10

अंतरणकर्ता राष्ट्र पर सजा पूरी करने का प्रभाव

जब इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1(क) के तहत प्राप्तकर्ता राष्ट्र अंतरणकर्ता राष्ट्र को यह अधिसूचित करता है कि सजा पूरी हो गई है, इस प्रकार की अधिसूचना के परिणामस्वरूप अंतरणकर्ता राष्ट्र में उस सजा से छुटकारा मिल जाएगा।

अनुच्छेद-11**निर्णय की समीक्षा एवं क्षमा, राजक्षमा अथवा सजा का रूपांतरण**

1. अंतरणकर्ता राष्ट्र को अकेले ही निर्णय की समीक्षा के लिए किसी आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।
2. कोई भी संविदाकारी राष्ट्र अपने संविधान अथवा अन्य कानून के अनुरूप सजा के लिए क्षमा, राजक्षमा दे सकता है या सजा को रूपांतरित कर सकता है।

अनुच्छेद-12**सजा के प्रवर्तन की समाप्ति**

1. अंतरणकर्ता राष्ट्र अपने भू-भाग में लिए गए किसी निर्णय के बारे में प्राप्तकर्ता राष्ट्र को तुरंत अधिसूचित करेगा जिसमें सजा अथवा उसके किसी भाग के प्रवर्तन की समाप्ति का उल्लेख हो।
2. प्राप्तकर्ता राष्ट्र को जैसे ही अंतरणकर्ता राष्ट्र द्वारा लिए गए किसी ऐसे निर्णय अथवा कार्रवाई की सूचना मिलती है जिसके परिणामस्वरूप सजा को लागू नहीं किया जा सकेगा तो प्राप्तकर्ता राष्ट्र सजा अथवा इसके भाग के प्रवर्तन को रद्द कर देगा।

अनुच्छेद-13**सजा लागू किए जाने संबंधी सूचना**

प्राप्तकर्ता राष्ट्र अंतरणकर्ता राष्ट्र को अधिसूचित करेगा:-

- (क) जब सजा का प्रवर्तन पूरा हो जाए; अथवा
 - (ख) यदि सजा पूरी होने से पूर्व ही सजायाफ्ता व्यक्ति कैद से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता राष्ट्र उसकी शेष सजा को भुगतने के लिए उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा प्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत उस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने की कार्रवाई करेगा।
- (1) यदि अंतरण करने वाले राष्ट्र के लिए अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता राष्ट्र सजा लागू करने के संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद-14**पारगमन**

- (1) यदि कोई संविदाकार राष्ट्र सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे राष्ट्र के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था करता है तो अन्य संविदाकारी राष्ट्र पारगमन की अनुमति से इन्कार करने के निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर इस प्रकार की व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने भूक्षेत्र से होकर अंतरित किए जाने वाले सजायाफ्ता व्यक्तियों के पारगमन को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करेगा: -
 - (क) यदि सजायाफ्ता व्यक्ति उसी देश का राष्ट्रिक है; अथवा
 - (ख) यदि किए जाने वाले अनुरोध से संविदाकार राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था अथवा अन्य अनिवार्य हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- (2) इस प्रकार का अंतरण करने की सहमति देने वाला संविदाकारी राष्ट्र इस प्रकार के पारगमन के संबंध में अग्रिम सूचना दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को देगा।

अनुच्छेद-15**लागत**

इस करार को लागू किए जाने पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन, अंतरणकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र में हुए व्यय को छोड़कर, प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा किया जाएगा। तथापि, प्राप्तकर्ता राष्ट्र सजायाफ्ता व्यक्ति से अथवा अन्य स्रोत से अंतरण पर आनेवाली पूरी अथवा आंशिक लागत को पूरा करने की मांग कर सकता है।

अनुच्छेद-16**भाषा**

अनुरोध तथा सहायक दस्तावेज प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्र की राजभाषा में होंगे जिनके साथ इनका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा।

अनुच्छेद-17**लागू होने का दायरा**

यह करार इस करार के लागू होने के पूर्व अथवा बाद में दी गई सजा के प्रवर्तन पर लागू होगा।

अनुच्छेद-18**विवादों का निपटान**

- (1) केंद्रीय प्राधिकरण इस करार के निर्वचन, प्रवर्तन अथवा कार्यान्वयन के क्रम में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद का समाधान पारस्परिक सहमति से करने का प्रयास करेंगे।
- (2) यदि केंद्रीय प्राधिकरण पारस्परिक सहमति से इस विवाद का निपटान करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो इसका समाधान राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा।

अनुच्छेद-19**सजायाफ्ता व्यक्तियों का सौंपा जाना**

अंतरणकर्ता राष्ट्र द्वारा सजायाफ्ता व्यक्तियों का अंतरण प्राप्तकर्ता राष्ट्र एवं अंतरणकर्ता राष्ट्र के बीच हुई सहमति से निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। प्राप्तकर्ता राष्ट्र कैदियों को अंतरणकर्ता राष्ट्र से ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा और वही अंतरणकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र के बाहर सजायाफ्ता व्यक्ति की हिरासत के लिए भी जिम्मेदार होगा।

अनुच्छेद-20**संशोधन**

संविदाकारी राज्यों के बीच हुई सहमति से इस करार में किया गया कोई संशोधन अथवा सुधार उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह करार।

अनुच्छेद-21**अंतिम प्रावधान**

यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार इस करार को लागू करने के लिए अनिवार्य अपनी विधिक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर राजनयिक चैनल के माध्यम से जल्द से जल्द लिखित में अन्य पक्षकार को सूचित करेगा। यह करार अंतिम अधिसूचना की तारीख से दूसरे महीने के पहले दिन से लागू होगा।

1. यह करार अनिश्चित समय के लिए लागू रहेगा। इसे किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा अन्य संविदाकारी पक्षकार को इसकी समाप्ति की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। यह समाप्ति ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छः महीने बाद प्रभावी होगी।
2. समाप्ति के बावजूद, यह करार उन सजायाफ्ता व्यक्तियों की सजा के संबंध में लागू रहेगा जिन्हें इस करार के तहत इस प्रकार की समाप्ति के प्रभावी होने की तारीख से पूर्व अंतरित किया गया है।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में अगस्त, 2017 के पहले दिन हिंदी और अंग्रेजी के दो-दो मूल पाठों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

नाम:

पदनाम:

सोमालिया संघीय गणराज्य की

सरकार की ओर से

नाम:

पदनाम:

[फा. सं. वी-17011/9/2017-पीआर]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(WOMEN SAFETY DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2019

G.S.R. 811(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the Federal Republic of Somalia. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Government of the Republic of India and the Government of the Federal Republic of Somalia on 1.8.2017 is given below. The Agreement was ratified by the Government of the Republic of India on 1.9.2017 and by the Government of the Federal Republic of Somalia on 14.10.2017.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of India and the Government of the Federal Republic of Somalia, hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreign nationals, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences in their own society;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1**Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “receiving State” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) “transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

ARTICLE 2**General Principles**

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.

2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State.

ARTICLE 3**Central Authorities**

1. Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
 - For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
 - For the Federal Republic of Somalia: Ministry of Justice
2. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

ARTICLE 4**Conditions for transfer**

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
 - (a) the person is a national of the receiving State;
 - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
 - (c) the judgment is final;
 - (d) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State in which his presence is required;
 - (e) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
 - (f) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
 - (g) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
 - (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other essential interest of the transferring State;
 - (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
 - (j) the transferring and receiving States agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

ARTICLE 5**Obligation to furnish information**

1. If the sentenced person has expressed an interest to the transferring State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
 - (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the receiving State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and Fingerprints of the Sentenced Person, as possible;
 - (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
 - (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
 - (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
 - (e) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;

- (f) any other information which the receiving State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
 - (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State;
 - (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence; and
 - (i) A statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the Sentenced Person.
2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
 - (b) a copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the transferring State constitute a criminal offence according to the law of the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
 - (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
 - (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
 - (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

ARTICLE 6

Requests and replies

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed by the Central authority of the transferring State through diplomatic channels to the Central Authority of the receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.
2. The receiving State shall promptly inform the transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

ARTICLE 7

Consent and its verification

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 8

Effect of transfer for the receiving State

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

ARTICLE 9

Continued enforcement of sentence

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the receiving State, that State may, with the prior consent of the transferring State, by court or administrative order, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the transferring State.

ARTICLE 10

Effect of completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring state under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging the sentence in the transferring state.

ARTICLE 11

Review of judgment and Pardon, amnesty or commutation

1. The transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment.
2. Either of the contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its constitution or other laws.

ARTICLE 12

Termination of enforcement of sentence

1. The Transferring State shall promptly notify the Receiving State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 13

Information on enforcement of sentence

1. The receiving State shall notify the transferring State:
 - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
 - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State shall take measures to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/ her liable for committing an offence under the relevant law of the receiving State.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

ARTICLE 14

Transit

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit;

- (a) if the sentenced person is one of its own nationals;
 - (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 15

Costs

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

ARTICLE 16

Language

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

ARTICLE 17

Scope of Application

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 18

Settlement of Disputes

- (1) The Central Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

ARTICLE 19

Handing Over of Sentenced Persons

The handing over of the transferred person by the transferring State to the receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the transferring and receiving State. The receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.

ARTICLE 20

Amendments

Any amendment or modification to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

ARTICLE 21

Final Provisions

1. This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.
2. The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.

3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoners who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on the 1st day of August 2017, in two originals each in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.

**For the Government of
the Republic of India**

**For the Government of the Federal
Republic of Somalia**

Name :

Name :

Designation :

Designation :

[F. No. V-17011/9/2017-PR]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.